पीपुल्स समाचार, भोपाल
23 JUN 2011

काबिले तारीफ है प्रदेश सरकार का यह कदम

यह तो वक्त ही बताएगा कि साहूकार इस लाइसेंस से नख और दंत विहीन होते हैं या फिर और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं।

आजाद हिंदुस्तान की सरकारों को छह दशक बाद किसानों की सुध लेने और साहूकारों पर लगाम कसने की फिक्र हो आई है। चहुंओर ऐलान हो रहा है कि अब साहूकारों के चंगुल से किसानों को निजात मिल जाएगी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे साहूकारी कानून में बदलाव करके ऐसा किया जाएगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि साहूकार इस लाइसेंस से नख और दंत विहीन होते हैं या फिर और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। बहरहाल मध्यप्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद ने साहूकारी अधिनियम 1934 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है और अगले माह विधानसभा में इसे पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद साहूकारी कानून को अमली जामा पहनाने के रास्ते साफ हो जाएंगे। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्यप्रदेश से पहले महाराष्ट्र में किसानों की पहाड़नुमा समस्याओं का हल भी कुछ इसी तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने खोजने की कोशिश की थी। वहां सरकारें बदल गईं लेकिन किसान अपने को समस्याग्रस्त ही पा रहा है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों पर पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा ने तो किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देने जैसा अभियान भी चलाया। अब यह अलग बात है कि पंजाब के किसानों को बैंक से कहीं अधिक साहूकारों पर भरोसा होने के कारण लाभ कुछ कम ही मिला, लेकिन यह क्या कम है कि सद्विचार के साथ जनहित के लिए प्रयास तो किए गए। इसी तर्ज पर अब जबकि मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार किसानों की आत्महत्याओं को साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबने का नतीजा मान चुकी है तो आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे किसानों और गरीबों के हालात सुधर सकें। इसके लिए जरूरी है कि जब साहूकारी कानून को लागू किया जाए तो प्रदेश का प्रत्येक जागरूक नागरिक किसानों तक उसकी सूचना पहुंचाने का काम इंसानी धर्म समझ कर करे। संभवतः ऐसा करने से आने वाले समय में हम अनेक लोगों को असमय मौत के गाल में समाने से रोक सकेंगे। यही नहीं जो किसान पहले से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनके बारे में भी शिवराज सरकार ने बेहतर विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। इस देर आयद दुरुस्त आयद की शैली में किया गया सरकार का यह कदम तारीफ के काबिल तो है ही।